सोमवार, 02 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

सूर्या ने रचा इतिहास टी20I में पूरे किए 3 हजार रन

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राम चरण और उपासना के घर जुड़वा बच्चों का जन्म

Page-05

जानिए बजट में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में साल 2026-27 का आम बजट पेश किया। यह उनके कार्यकाल का लगातार 9वां बजट भाषण है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया से जुड़े प्रमुख कदम शामिल हैं।निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि बजट का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और आम जनता के लिए सुविधाएँ बढ़ाना है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और फंडिंग के ऐलान किए, जिससे रोजगार, तकनीकी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।इस बजट में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर नई पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त फंडिंग जैसी घोषणाएँ भी की गईं।वित्त मंत्री ने विशेष रूप से कहा कि यह

भारत ने आईटी और टेलीकॉम पर लगाया बड़ा दांव
अमेरिका-चीन-रूस-पाकिस्तान के आगे कितना दमदार

भारत सरकार ने बजट 2026 में आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। टेलीकॉम क्षेत्र के लिए 74,560 करोड़ रुपये (लगभग 8 बिलियन डॉलर) का सीधा आवंटन किया गया है, जबकि आईटी सेक्टर के लिए विदेशी क्लाउड कंपनियों को 20 साल का टैक्स हॉलीडे जैसी बड़ी राहत दी गई है। इस कदम को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।बजट में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा हिस्सा रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत में 5G और भविष्य की तकनीकों का तेजी से विस्तार हो और देश आईटी सेवाओं के साथ-साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बने।विशेषज्ञों का कहना है कि

हालांकि अमेरिका और चीन की तुलना में भारत का निवेश अभी छोटा है, लेकिन नीति आधारित प्रोत्साहन और टैक्स राहत के माध्यम से भारत डिजिटल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकता है।यह बजट न सिर्फ निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि नए रोजगार और तकनीकी नवाचार के अवसर भी पैदा करेगा।

बजट 2026 में किसे मिला सबसे ज्यादा पैसा?:
देखें सभी योजनाओं की फंडिंग लिस्ट

शिक्षा मंत्रालय:स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा फंड का आवंटन किया गया। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और ई-लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय:ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में पर्याप्त संसाधन रखे गए हैं। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण, अस्पतालों में तकनीकी उपकरणों की खरीद और टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

सड़क और परिवहन मंत्रालय:राष्ट्रीय और राज्य हाईवे परियोजनाओं के साथ-साथ लोक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटित किया गया है।

डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षा:डिजिटल इंडिया मिशन और साइबर सुरक्षा के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसमें सरकारी

डेटा सुरक्षा और ई-गवर्नेंस सुधारों पर फोकस किया गया है।

कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास:कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका योजनाओं के लिए फंड आवंटित किया गया है। इसमें किसानों के लिए नई तकनीक, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं।

सेफ्टी से हाई-स्पीड रेल तक:
बजट 2026 में रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी विजन का खुलासा

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट 2026-27 को लेकर रेल मंत्रालय के प्रमुख लक्ष्यों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फोकस सिर्फ़ रेल नेटवर्क के विस्तार पर नहीं है, बल्कि सुरक्षा, तकनीकी आधुनिकीकरण और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं को नई गति देने पर है।वैष्णव ने बताया कि बजट में रेल मंत्रालय के लिए अलग से आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा सुरक्षा उपायों, ट्रैक अपग्रेडेशन और डिजिटल signaling सिस्टम के लिए रखा गया है। इसके अलावा, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और हवाई-पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।रेल मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक भारत के प्रमुख शहरों को हाई-स्पीड रेल से जोड़ा जाए और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। इसके लिए टेक्नोलॉजी और आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।"उन्होंने यह भी बताया कि बजट में पूर्वोत्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि लोगों को किफायती और समय पर परिवहन सुविधा मिले।विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से भारत के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नई जान आएगी, और नई परियोजनाओं से रोज़गार और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।बजट भाषण के बाद, रेल मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक इन्फोग्राफिक और विज़ुअल रोडमैप भी जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से सुरक्षा उपायों, हाई-स्पीड रेल और ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए फंड का उपयोग किया जाएगा।अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार की योजना केवल ट्रेनों को तेज़ करना नहीं है, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट

इकोसिस्टम को आधुनिक और सुरक्षित बनाना है, जिससे जनता को बेहतर अनुभव और निवेशकों को स्थिरता मिल सके।रेल मंत्रालय डिजिटलाइजेशन को भी प्राथमिकता दे रहा है। मंत्री ने बताया कि सिग्नलिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम्स और ट्रैक मॉनिटरिंग को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इससे न सिर्फ़ सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रेन संचालन में देरी को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।वैष्णव ने कहा कि हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी सरकार का विजन है कि आने वाले वर्षों में भारत में यूरोप और जापान जैसी आधुनिक रेल सुविधाएँ उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट ट्रेनों पर विशेष जोर दिया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के इन उपायों से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि रोज़गार, आर्थिक विकास और निवेशकों की रुचि भी बढ़ेगी। रेलवे क्षेत्र में नई परियोजनाओं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत वैश्विक स्तर पर एक आधुनिक और सुरक्षित रेल नेटवर्क वाला देश बन सकता है।रेल मंत्री ने अंत में कहा, "हमारा लक्ष्य केवल ट्रेनों को तेज़ करना नहीं है, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को आधुनिक और सुरक्षित बनाना है। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और निवेशकों को स्थिरता मिलेगी।"रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि नए ट्रेन प्रोजेक्ट्स में स्थानीय निर्माण और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा।विद्युतीकरण और ऊर्जा-कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे रेल संचालन लागत कम होगी।मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्टेशन अपग्रेडेशन और स्मार्ट सुविधाओं पर भी निवेश होगा।रेल सुरक्षा बल और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करके दुर्घटना रोकने पर जोर दिया जाएगा।

बजट में आम आदमी को राहत:
दवाइयों और पर्सनल आयात पर कस्टम ड्यूटी में कटौती

बजट 2026-27 में आम आदमी के लिए कस्टम ड्यूटी में राहत के कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं — सबसे बड़ा बदलाव यह है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सामानों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को पहले की 20% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया गया, जिससे विदेश से मंगाए जाने वाले व्यक्तिगत सामान (जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) की कुल लागत कम होगी और आम उपभोक्ता को सीधा फायदा मिलेगा; साथ ही सरकार ने कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ी 17 दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है और कुछ दुर्लभ रोगों की दवाओं को भी ड्यूटी-फ्री कर दिया, जिससे रोगियों के लिए इन महत्वपूर्ण दवाइयों की कीमतें कम होने की उम्मीद है।इसके अलावा, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर ड्यूटी में कटौती से रोजमर्रा के गैजेट्स (जैसे हेडफोन, स्मार्टवॉच और पोर्टेबल डिवाइसेस) की कीमतों में राहत मिल सकती है।

खामेनेई का इशारा: अगर कोई सैन्य फैसला हुआ

तो पूरा मध्य पूर्व बनेगा युद्ध का मैदान

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर कोई भी सैन्य हमला पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है।बढ़ते तनाव के बीच यह बयान क्षेत्रीय स्थिरता, तेल आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत माना जा रहा है।

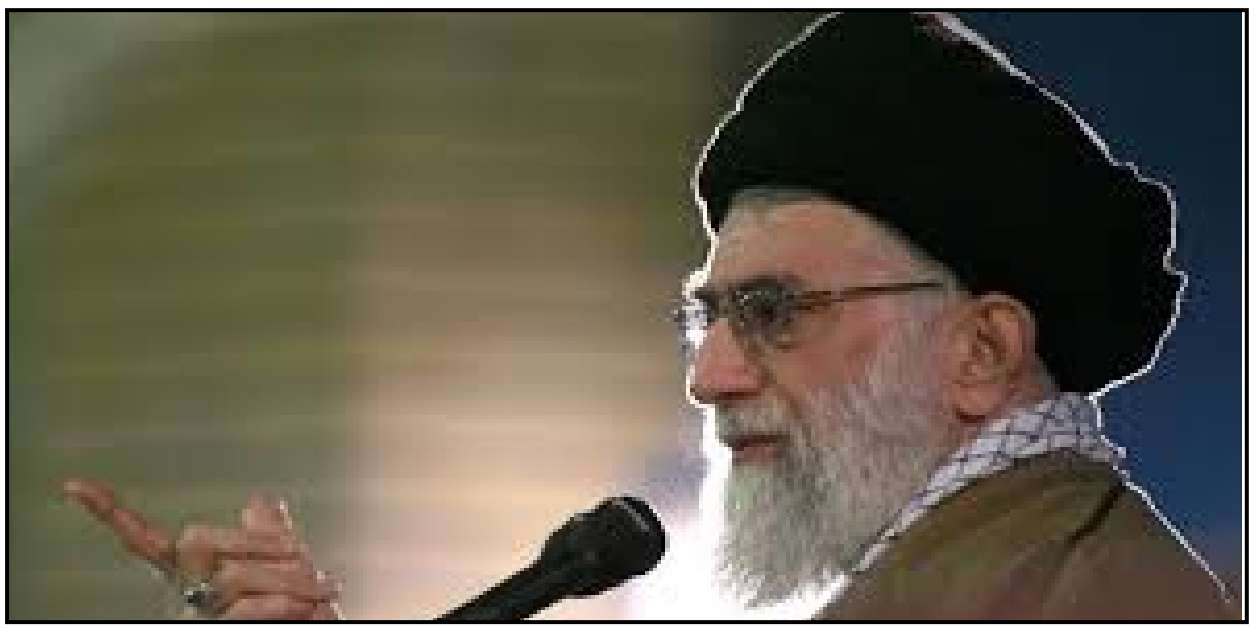

ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ा संदेश भेजा है कि अगर कोई गलत सैन्य फैसला लिया गया और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो यह संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा – बल्कि पूरी मध्य पूर्व (Middle East) एक बड़े युद्ध का दृश्य बन जाएगा। यह चेतावनी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और क्षेत्र में अमेरिकी USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत समेत युद्धपोतों का निर्माण बढ़ा दिया गया है। खामेनेई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्र युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता, मगर अगर किसी ने उन्हें हमला किया या परेशान किया, तो वे कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा, "अमेरिकियों को यह जान लेना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करेंगे, तो यह मामला सिर्फ सीमा के अन्दर नहीं रहेगा – यह पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा और एक क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत होगी।"इस चेतावनी को बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यहाँ न केवल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, बल्कि सरकारी स्रोतों ने भी कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण काफी संवेदनशील हो गया है। धीरे-धीरे सेना-संबंधित गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है और सामरिक नौसैनिक शक्ति का निर्माण भी जारी है।डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि उनका प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना चाहता है और अगर वह सैन्य विकल्प से बचा नहीं जाता है तो बलपूर्वक कार्रवाई भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। वहीं, ईरानी अधिकारियों का मानना है कि किसी भी सैन्य हमले का जवाब शक्तिशाली ढंग से दिया जाएगा। हालाँकि ट्रंप और तेहरान दोनों के बीच राजनयिक बातचीत भी जारी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे मिसाइल कार्यक्रम और सैन्य नियंत्रण के प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, ये भी विकसित भारत का महत्वपूर्ण पहलू है।

Union Budget 2026: रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ी

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) रिवाइज करने की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. अब करदाता मामूली फीस देकर 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक रिटर्न रिवाइज कर सकेंगे. इससे गलतियों को सुधारने और अनावश्यक पेनल्टी से बचने में मदद मिलेगी.वित्त मंत्री ने आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा को भी अलग-अलग करने का प्रस्ताव रखा है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा. सरकार का उद्देश्य रिटर्न प्रोसेसिंग को सुचारु और टैक्सपेयर्स के लिए सुविधाजनक बनाना है.छोटे करदाताओं के लिए सरकार एक नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस शुरू करने जा रही है. इसके तहत असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन किए बिना कम या शून्य डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा. इससे अनुपालन सरल होगा और समय की बचत होगी.

सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन लाने की योजना है.वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ISM 2.0) की शुरुआत करेगी.

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को दिखाया कड़ा संदेश

भारत ने बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने सटीक कूटनीतिक और राजनयिक कदमों के जरिए पाकिस्तान को इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की नीति और बलूचिस्तान में उत्पीड़न को उजागर किया है। भारत ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग शांति, सुरक्षा और विकास के हकदार हैं, और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान को यह दिखाने के लिए है कि भारत केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दबाव के माध्यम से भी इस मामले को उठा सकता है। इसके अलावा भारत ने सीमा पार गतिविधियों और आतंकवाद को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है।राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारत का यह रुख क्षेत्रीय स्थिरता और मानवाधिकार

सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह संदेश पाकिस्तान के आक्रामक रवैये को रोकने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी मदद करेगा।साथ ही, भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान से जुड़े संभावित खतरों के मद्देनजर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में बलूच आंदोलन और आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए सीमा पर अतिरिक्त निगरानी और तैयारियों की जरूरत है।बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत की कूटनीतिक पहल को अंतरराष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी प्रमुखता दी है।

आयातित वस्तुएं होंगी किफायती, बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती

केंद्रीय बजट में इस बार आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की गई है। सरकार ने कई आयातित वस्तुओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) में कमी करने का फैसला किया है, जिससे विदेश से आने वाले सामान अब पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मशीनरी, मेडिकल उपकरणों और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर देखने को मिल सकता है।वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह कदम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने, उद्योगों की लागत कम करने और आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई ऐसे कच्चे माल और कंपोनेंट्स, जो भारत में तैयार उत्पाद बनाने के लिए आयात किए जाते हैं, अब कम शुल्क पर उपलब्ध होंगे। इससे घरेलू उत्पादों की लागत भी घट सकती है।सरकार का यह कदम वैश्विक व्यापार के साथ भारत के संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। कम ड्यूटी से आयात-निर्यात संतुलन, सप्लाई चेन स्थिरता और उत्पादन क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही, यह निर्णय भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी एक कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर, बजट में कस्टम ड्यूटी में की गई कटौती को उद्योग और उपभोक्ता दोनों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में बाजार में कई आयातित और उनसे जुड़े घरेलू उत्पादों की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है।

राहुल गांधी ने बजट पर साधा निशाना, कहा- सरकार ने देश के आर्थिक संकट को अनदेखा किया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम जनता और गरीब तबके की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बजट में केवल बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट सेक्टर के हितों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि छोटे व्यवसाय, किसानों और मजदूर वर्ग के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए। राहुल गांधी ने कहा, "देश वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएँ पूरी तरह बदल गई हैं। आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी गई।" उन्होंने बजट में दी गई घोषणाओं को दूरदर्शिता में कमी और आम नागरिक के लिए कम असरदार बताया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब में कहा कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बजट के माध्यम से छोटे किसानों, स्टार्टअप्स, महिला

उद्यमियों और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विशेष कदम उठाए गए हैंकांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी बजट की आलोचना की। माकपा ने कहा कि बजट में केवल भारी उद्योगों और बड़े व्यापारियों को फायदा पहुँचाया गया है, जबकि आम नागरिकों के लिए राहत नगण्य है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विपक्ष इस बजट को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बजट में सरकार की नकली और दिखावटी घोषणाओं से आम जनता का भरोसा कम होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए।

संपादक की कलम से

भारत का केंद्रीय बजट 2026–27 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया, और यह देश की आर्थिक नीति की दिशा तय करने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। इस बजट में विकास, समावेशन और पुनर्गठन के बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, लेकिन आशाएँ और वास्तविक प्रभाव अलग-अलग वर्गों — किसानों, मध्यम वर्ग और युवाओं — के जीवन पर अलग तरह से पड़ेंगे। सबसे पहले बात करें आर्थिक आकड़ों की दिशा की। इस बार पब्लिक कैपेक्स (सरकारी पूंजीगत व्यय) को लगभग ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, ताकि बुनियादी ढांचे को मजबूत कर भारत की विकास गति को बरकरार रखा जा सके। साथ ही, राजकोषीय घाटा को लगभग 4.3–4.4 % के स्तर पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो संकेत देता है कि सरकार आर्थिक स्थिरता और निवेश-प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।किसानों के लिए यह बजट एक रणनीतिक रुख दिखाता है। कृषि-क्षेत्र को लगभग ₹1.63 लाख करोड़ का आवंटन दिया गया है, जिसमें यह जोर दिया गया है कि खेती अब केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं रहे — उच्च-मूल्य फसलें जैसे नारियल, काजू, कोको, चंदन एवं पशुपालन तथा मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में रोजगार और आय को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही Bharat-VISTAAR नामक बहुभाषी AI-आधारित डिजिटल मंच किसानों को मौसम, मंडी भाव और कृषि सलाह उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया है, जिससे उनके निर्णय अधिक सूचित और लाभकारी बन सकें।
हालाँकि यह पहल तकनीकी रूप से सकारात्मक लगती है, लेकिन कृषि की बुनियादी चुनौतियाँ — जैसे सिंचाई की व्यापक पहुँच, भूमि एवं जल संरचना में सुधार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की विश्वसनीयता — अभी भी ऐसे क्षेत्रों हैं जहाँ जमीनी असर तुरंत दिखना बाकी है। कुछ समीक्षाएँ यह भी इंगित करती हैं कि कृषि बजट का हिस्सा कुल राष्ट्रीय व्यय में अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है, जिससे "किसान-पहला बजट" के दावे पर बहस जारी है। मध्यम वर्ग तथा आम टैक्सपेयर्स के लिए बजट प्रत्यक्ष टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता, जिससे तुरंत कर राहत सीमित है। हालांकि टैक्स प्रशासन में सुधार, TCS-TDS नियमों में सरलीकरण और कुछ विशेष कल्याणकारी प्रावधानों से टैक्स कम्प्लायंस में आसानी तथा कुछ वर्गों के लिए अप्रत्यक्ष राहत की उम्मीद बनती है। उन्मुख और समावेशी बजट बताया है, वहीं विपक्ष एवं सामाजिक-आर्थिक आलोचक इसे अमीर-समर्थक और गरीब/मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बताने वाले स्वर भी रहे हैं।

बजट 2026 का असर: शेयर बाजार में हाहाकार

सेंसेक्स 2300 अंक टूटा, निवेशकों की उम्मीदें टूटीं

बजट 2026 का निवेशकों को बेसब्री से इंतजार था, वही दलाल स्ट्रीट के लिए किसी 'ब्लैक संडे' में तब्दील हो गया।

बजट 2026 के ऐलान के बाद शेयर बाजार में निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 के कुछ फैसलों ने बाजार में भारी बेचैनी पैदा कर दी। खासकर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ोतरी की घोषणा ने निवेशकों की धारणा को झटका दिया। इसके चलते सेंसेक्स में एक झटके में 2300 अंकों की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी भी पिछले सत्र की तुलना में 700 अंक नीचे बंद हुआ।बाजार में

गिरावट के तीन बड़े कारण:

F&O पर टैक्स में वृद्धि: सरकार ने फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है। सेबी (SEBI) की हालिया रिपोर्ट्स में बार-बार चेतावनी दी गई थी कि 90% से अधिक रिटेल ट्रेडर्स F&O में पैसा गंवा रहे हैं। इसे हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने टैक्स का सहारा लिया है।

कैपिटल गेन्स का डर: निवेशकों को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में राहत मिलेगी, लेकिन बजट में इस मोर्चे पर कोई बड़ी ढील न मिलने से निराशा बढ़ गई।

राजकोषीय घाटा और बॉन्ड यील्ड: राजकोषीय घाटे के आंकड़ों और बॉन्ड यील्ड में उछाल ने बैंकिंग शेयरों पर दबाव डाला, जिससे निफ्टी बैंक भी बुरी तरह टूट गया।बजट भाषण के बीच ही सेंसेक्स और निफ्टी ने गोता लगाना शुरू कर दिया। सेंसेक्स 2300 अंकों की गिरावट के साथ 80,000 के स्तर के नीचे खिसक गया, वहीं निफ्टी 50 में भी 700 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कुछ ही मिनटों के भीतर निवेशकों के लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान बैंकिंग, आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा मार पड़ी।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से बाजार में लिक्विडिटी कम हो सकती है। शॉर्ट टर्म में बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। हालांकि, सरकार का तर्क है कि इससे निवेशक 'गेमिंग' के बजाय लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित होंगे।बजट 2026 के ऐलान के बाद शेयर बाजार में निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 के कुछ अहम फैसलों ने बाजार में भारी बेचैनी पैदा कर दी। खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ोतरी की घोषणा ने निवेशकों की धारणा को गहरा झटका दिया। नतीजतन, सेंसेक्स एक ही झटके में 2300 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया, जबकि निफ्टी पिछले सत्र के मुकाबले करीब 700 अंक नीचे बंद हुआ।

F&O पर टैक्स में वृद्धि:

> केंद्रीय बजट 2026-27 ऐसे समय में पेश किया गया है, जब भारतीय शेयर बाजार पहले से ही ऊंचे वैल्यूएशन, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और महंगाई को लेकर चिंताओं के दौर से गुजर रहा था। निवेशकों को सरकार से टैक्सेशन में राहत, कैपिटल मार्केट को प्रोत्साहन और ग्रोथ-फ्रेंडली कदमों की उम्मीद थी।

सरकार ने फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सेबी (SEBI) की हालिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि 90 फीसदी से अधिक रिटेल निवेशक F&O ट्रेडिंग में नुकसान उठा रहे हैं। सरकार का मानना है कि टैक्स बढ़ाने से सट्टा प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी और रिटेल निवेशकों को जोखिम भरे सौदों से दूर किया जा सकेगा। हालांकि, बाजार ने इस फैसले को नकारात्मक रूप में लिया, क्योंकि इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी घटने की आशंका बढ़ गई है।निवेशकों को उम्मीद थी कि बजट 2026 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में राहत दी जाएगी, जिससे इक्विटी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन बजट में इस मोर्चे पर कोई ठोस राहत नहीं मिलने से बाजार की उम्मीदें टूट गईं। कई निवेशक इसे इक्विटी बाजार के प्रति सरकार के सख्त रुख के तौर पर देख रहे हैं।

बजट में पेश किए गए राजकोषीय घाटे के आंकड़ों और सरकारी बॉन्ड यील्ड में आई तेजी ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव बढ़ा, क्योंकि इससे फंडिंग कॉस्ट बढ़ने की आशंका रहती है। इसका सीधा असर निफ्टी बैंक पर पड़ा, जो दिन के कारोबार में बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ।बजट भाषण शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2300 अंकों से ज्यादा गिरकर 80,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी 50 में 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ ही घंटों के भीतर निवेशकों की लाखों करोड़ रुपये की बाजार पूंजी साफ हो गई।सेक्टरवार बात करें तो बैंकिंग, आईटी और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी भारी दबाव रहा, जिससे रिटेल निवेशकों को दोहरी मार झेलनी पड़ी।बाजार में गिरावट के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी मुनाफावसूली तेज कर दी। माना जा रहा है कि टैक्स ढांचे में बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते विदेशी निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने कुछ हद तक गिरावट संभालने की कोशिश की, लेकिन बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा था कि बाजार संभल नहीं सका।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि F&O पर टैक्स बढ़ने से शॉर्ट टर्म में बाजार की लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है और अस्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि लंबी अवधि में यह कदम बाजार को ज्यादा स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि इससे सट्टेबाजी कम होगी और निवेशक मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों की ओर रुख करेंगे।सरकार का तर्क है कि इन उपायों का मकसद निवेश को "गेमिंग" की बजाय दीर्घकालिक और सुरक्षित दिशा में ले जाना है। आने वाले दिनों में बाजार इस नए टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे पचाता है, इस पर निवेशकों और विश्लेषकों की नजर बनी रहेगी।विश्लेषकों का कहना है कि बजट के बाद बाजार की यह तीखी प्रतिक्रिया बताती है कि निवेशक नीतिगत स्थिरता और टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे थे

चुनावी तैयारियों को रफ्तार:

केंद्रीय बजट में निर्वाचन आयोग का फंड 25.33% बढ़ा

आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में निर्वाचन आयोग के लिए आवंटित धनराशि में 25.33 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त बजट से चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक-सक्षम बनाया जा सकेगा।बजट में की गई यह वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वीवीपैट की उपलब्धता, उनके रखरखाव, और सुरक्षित भंडारण जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में उपयोग की जाएगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने, दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम करने पर भी फोकस रहेगा।सूत्रों के मुताबिक, इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा बलों की तैनाती और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त रह सके।सरकार का कहना है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम है और उसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, लगातार बढ़ते चुनावी खर्च और तकनीकी आवश्यकताओं के मद्देनज़र यह बढ़ोतरी समय पर उठाया गया कदम है।हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट आवंटन के साथ-साथ उसके प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग की निगरानी पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि उनके सही इस्तेमाल से सुनिश्चित होती है।कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट में निर्वाचन आयोग के लिए बढ़ाया गया यह फंड आने वाले चुनावी महीनों में देश की चुनावी व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते मतदाता आंकड़ों और चुनावी प्रक्रियाओं की जटिलता को देखते हुए यह वित्तीय सहयोग आवश्यक हो गया था।इससे न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि चुनावी व्यवस्था में जनता का भरोसा भी और मजबूत होगा।आगामी चुनावों से पहले यह बजट बढ़ोतरी निर्वाचन आयोग को पूरी तरह तैयार करने में अहम साबित हो सकती है।इस बढ़े हुए बजट से निर्वाचन आयोग को समयबद्ध और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

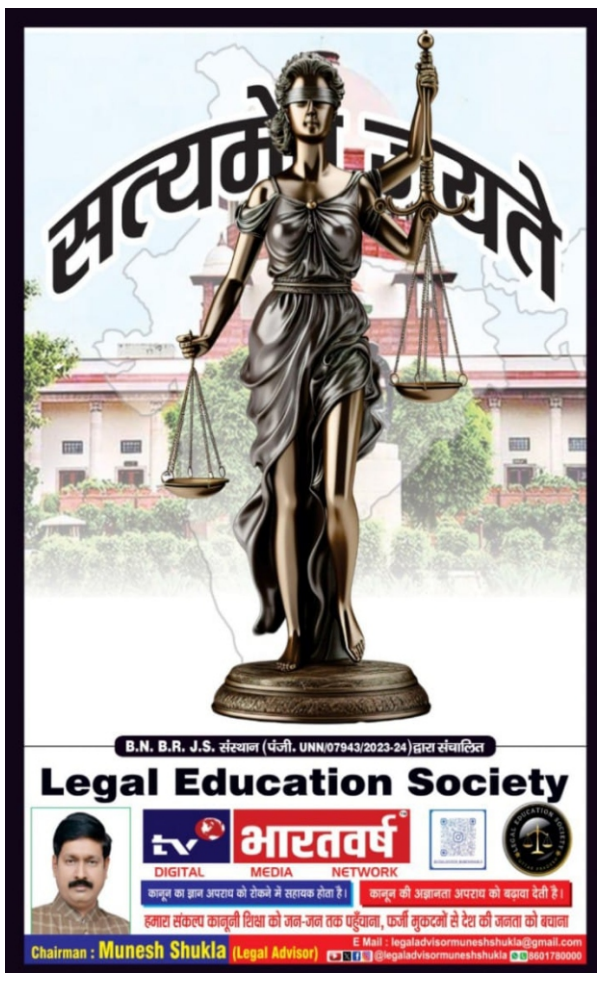

Budget 2026 में खेलों पर बड़ा दांव

बदलेगा पूरा Sports Ecosystem

बजट 2026-27 में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा के साथ खेल सामान सस्ते होने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार भारत को खेल सामग्री का वैश्विक केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार नौवीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने देश में उच्च गुणवत्ता वाले किफायती खेल सामानों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खेल सामानों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की अपार क्षमता है। इससे स्पष्ट होता है कि अब खेल सामान सस्ते होने वाले हैं, जो देश के खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

सीतारमण ने कहा कि खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026-27 भाषण में कहा कि भारत में खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता है। हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करते हैं। यह घोषणा देश में खेलों को बढ़ावा देने में मोदी सरकार द्वारा वर्षों से दिए जा रहे महत्व को उजागर करती है।

पिछले एक दशक में, भारतीय सरकार ने खेलों के प्रति अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है, प्रतिक्रियात्मक मॉडल से हटकर एक सक्रिय, खिलाड़ी-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर हुई है। यह विकास एक "पिरामिड" रणनीति द्वारा चिह्नित है: जमीनी स्तर पर नींव को मजबूत करना और शीर्ष स्तर पर अभिजात वर्ग को समर्थन प्रदान करना। अब ध्यान केवल स्टेडियम बनाने से हटकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित हो गया है। इसमें नया राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और भारत को खेल सामग्री का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की एक समर्पित पहल शामिल है। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में, बजट में खेलों के लिए भारी मात्रा में आवंटन किया गया है।बजट प्रस्तुति के दौरान बोलते हुए, सीतारमण ने खेल विनिर्माण के आधुनिकीकरण और अनुसंधान-आधारित नवाचार का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया ताकि भारत को उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। इस पहल से न केवल घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि खेल क्षेत्र में स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यमों और प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों के लिए अवसर भी सृजित होंगे। यह घोषणा क्षेत्र-विशिष्ट नवाचार रणनीतियों पर बढ़ते ध्यान को दर्शाती है, जो खेलों को न केवल एक सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधि के रूप में बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और तकनीकी अवसर के रूप में भी स्थापित करती है।

कानून शिक्षा में सुधार की जरूरत पर नई बहस — BCI नियम आधुनिककरण में बाधा

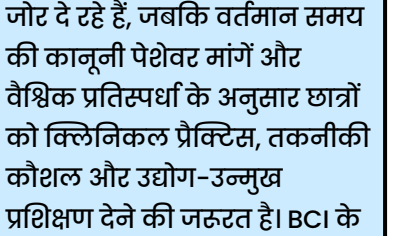

कानून शिक्षा (Legal Education) में सुधार की आवश्यकता को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने कहा है कि Bar Council of India (BCI) के वर्तमान नियम और दिशानिर्देश आधुनिक कानूनी शिक्षा के लिए बाधक बन रहे हैं। उनका कहना है कि BCI के नियम कानून स्कूलों के लिए बहुत सख्त, कठोर और पारंपरिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिससे शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रह गई है और नए कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करना कठिन हो रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने पर जोर दे रहे हैं, जबकि वर्तमान समय की कानूनी पेशेवर मांगें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुसार छात्रों को क्लिनिकल प्रैक्टिस, तकनीकी कौशल और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण देने की जरूरत है। BCI के सख्त नियम छात्रों को इंटर्नशिप, क्लिनिकल प्रोग्राम और नई विधिक टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण लेने से रोक रहे हैं।

पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर मचा हो हल्ला, आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने उठाए सवाल

यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स के साथ सीख, कौशल और रोजगार जुड़ेगें

केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में मुख्य औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के किनारे पाँच 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स' बनाने की घोषणा की है। ये टाउनशिप्स केवल शैक्षणिक संस्थान तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि इनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, स्किल-डेवलपमेंट सेंटर, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, आवासीय और खेल सुविधाएँ सभी को एक साथ विकसित किया जाएगा।इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा और रोजगार के बीच सीधा लिंक स्थापित हो। वर्तमान समय में शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक और कक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। उद्योग और तकनीकी क्षेत्र की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए, इस टाउनशिप मॉडल के माध्यम से छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव और व्यावसायिक कौशल से लैस किया जाएगा।विशेषकर विधिक शिक्षा और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों में इस पहल का महत्व अत्यधिक है। नए टाउनशिप्स में क्लिनिकल लॉ सेंटर, लॉ रिसर्च लैब्स, वर्चुअल कोर्ट रूम और इनडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम्स भी स्थापित किए जाएंगे। इससे छात्रों को न केवल सिद्धांत की पढ़ाई मिलेगी, बल्कि उन्हें वास्तविक केस स्टडीज और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी मिलेगा।

ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप से पहले बड़ा झटका, पेसर कमिंस बाहर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज नथम कमिंस किसी व्यक्तिगत कारण या फिटनेस समस्या के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके बाद कंगारू टीम ने अपनी अंतिम प्लेइंग इलेवन में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।टीम मैनेजमेंट ने कहा कि कमिंस के स्थान पर जेम्स पैटिनसन को शामिल किया गया है, जबकि बल्लेबाजी क्रम में भी मॉर्निंग स्टार बल्लेबाज मैक्सवेल को शुरुआती ऑर्डर में लाने का निर्णय लिया गया है। टीम के कोच ने कहा, "कमिंस का बाहर होना हमारी योजना में बदलाव लाता है, लेकिन हमारे पास सक्षम खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। हम टीम को पूरी तरह से विश्व कप के लिए तैयार करेंगे।"विशेषज्ञों का मानना है कि कमिंस की अनुपस्थिति ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी रणनीति पर असर डाल सकती है, खासकर तेज़ विकेटों और शुरुआती ओवरों में। वहीं बल्लेबाजी में बदलाव टीम को अधिक आक्रामक और संतुलित बनाने का प्रयास है।टीम के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमें चुनौती स्वीकार करनी होगी। हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूत बनाना है। कमिंस की कमी हमें मजबूर करती है कि हर सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ जाए।"इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब विश्व कप में उनका संतुलन और रणनीति बदलने की आवश्यकता है। मैच विश्लेषक मानते हैं कि अगर नई जोड़ी अच्छे प्रदर्शन में सफल होती है, तो टीम के लिए यह सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

सूर्या ने रचा इतिहास... टी20I में पूरे किए 3 हजार रन

यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें टी20I मैच के दौरान देखने को मिली, जहाँ सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 63 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए इस उपलब्धि को यकीनी बनाया। उनके इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वे टी20 क्रिकेट के सबसे ख़तरनाक और प्रभावशाली बल्लेबाज़ों में से एक हैं।सूर्यकुमार यादव अब T20I क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज़ बल्लेबाज बन गए हैं — गेंदों की संख्या के आधार पर यह उपलब्धि किसी और बल्लेबाज़ ने नहीं बनाई है। UAE के पूर्व रिकॉर्ड धारक मुहम्मद वसीम (1947 गेंदें) की तुलना में सूर्यकुमार ने यह मुक़ाम 125 गेंदें पहले हासिल किया।सूर्यकुमार यादव इस उपलब्धि के साथ अब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान भारतीय बल्लेबाज़ों के साथ एक विशेष सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने समय के साथ टी20I में विशेष उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हालांकि कोहली और रोहित जैसे दिग्गजों ने 3000 रन से अधिक रन पहले ही बना रखे हैं, सूर्यकुमार ने गेंदों के हिसाब से इसकी गति में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।सूर्यकुमार यादव का यह रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट की सबसे प्रतिस्पर्धात्मक प्रारूप में टीम इंडिया के लिये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर T20 World Cup 2026 से पहले उनके शानदार फॉर्म के कारण। उनकी बल्लेबाज़ी शैली, तेज़ स्ट्राइक रेट और शॉट-मेकर क्षमता ने उन्हें टी20 दुनिया में एक ख़तरा खिलाड़ी बना दिया है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस सीरीज के पांचवें मैच में सूर्यकुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में खुद का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। आपसी प्रतिस्पर्धा में ऐसी उपलब्धि का बनना टीम इंडिया के लिये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है।

बजट से निराश बाजार:

सेंसेक्स में 1546 अंकों की गिरावट, निफ्टी फिसलकर 25000 के नीचे"

बाजार की यह गिरावट केवल नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि यह निवेशकों को यह याद दिलाती है कि शेयर बाजार नीतिगत बदलावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। जहां अल्पकालिक अस्थिरता बनी रह सकती है, वहीं दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण रखने वालों के लिए यह अवसर भी बन सकता है।

स्थानीय शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में रविवार को दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बजट में जिंस वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव इसकी मुख्य वजह रही।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए पुनर्खरीद (बायबैक) से प्राप्त आय पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने की भी घोषणा की। शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बाद 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स ने वापसी लेकिन बजट प्रस्तुति के बीच यह अपनी बढ़त गंवा बैठा।कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 2,370.36 अंक या 2.88 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और यह 80,000 अंक के स्तर से नीचे टूटकर 79,899.42 अंक पर आ गया। 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 748.9 अंक या 2.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,571.75 अंक पर आ गया।सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 6.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय स्टेट बैंक, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और इटर्नल के शेयर भी गिरावट में रहे। सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर लाभ में रहे।एशियाई बाजार रविवार को अवकाश के कारण बंद रहेंगे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,251.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।इन घटनाओं के व्यापक प्रभाव को समझना जरूरी है। प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में बढ़ोतरी का सीधा असर उन निवेशकों और ट्रेडर्स पर पड़ता है जो कम मार्जिन पर उच्च वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं। जिंस वायदा बाजार में यह लागत वृद्धि हेजिंग गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकती है। कमोडिटी ट्रेडर्स, जो पहले ही वैश्विक कीमतों, मुद्रा विनिमय दरों और भू-राजनीतिक तनावों के जोखिम झेलते हैं, अब अतिरिक्त कर बोझ को भी अपनी रणनीति में शामिल करने के लिए मजबूर होंगे।बायबैक पर कर लगाने का फैसला भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने शेयर बायबैक को निवेशकों को रिटर्न देने के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया था। इससे शेयर की कीमतों को समर्थन मिलता था और प्रति शेयर आय (EPS) में सुधार होता था। अब यदि बायबैक से प्राप्त आय पर पूंजीगत लाभ कर लागू होगा, तो कंपनियां डिविडेंड या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती हैं। इससे कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट रणनीतियों में बदलाव संभव है।विश्लेषकों के अनुसार, बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया नकारात्मक जरूर रही, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव सेक्टर दर सेक्टर अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट मुख्यतः व्यापक बिकवाली के कारण रही, न कि किसी विशेष नीतिगत नुकसान के कारण। वहीं, रक्षा, अवसंरचना और फार्मा जैसे क्षेत्रों में चुनिंदा शेयरों ने मजबूती भी दिखाई, जो यह संकेत देता है कि निवेशक पूरी तरह से घबराहट में नहीं हैं बल्कि चयनात्मक रुख अपना रहे हैं।विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की भूमिका भी इस दौर में महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने पिछले सत्र में शुद्ध खरीदारी की थी, लेकिन बजट के बाद उनकी रणनीति में बदलाव संभव है। वैश्विक निवेशक अक्सर कर नीतियों, राजनीतिक स्थिरता और विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि कर ढांचा अधिक जटिल या महंगा हो रहा है, तो अल्पकालिक पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है।घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) आमतौर पर ऐसे समय बाजार को स्थिरता देने का काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां गिरावट के दौरान चुनिंदा गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश बढ़ाती हैं। यही वजह है कि भारी गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह ढहने के बजाय कुछ स्तरों पर सहारा पाता नजर आया।तकनीकी विश्लेषण के लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी का 25,000 स्तर से नीचे आना मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि बाजार आने वाले सत्रों में इस स्तर के ऊपर टिकने में सफल नहीं होता, तो और गिरावट की आशंका जताई जा रही है। वहीं, यदि वैश्विक संकेत सकारात्मक रहते हैं और घरेलू निवेशकों का भरोसा लौटता है, तो रिकवरी भी संभव है।वैश्विक कारक भी इस समय नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। अमेरिकी बाजारों में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति जैसे कारक भारतीय बाजारों की दिशा तय करने में भूमिका निभाते हैं। यदि वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उभरते बाजारों से पूंजी निकासी तेज हो सकती है।रिटेल निवेशकों के लिए यह समय भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय रणनीतिक सोच अपनाने का है। तेज गिरावट के दौरान घबराकर बिकवाली करने से नुकसान पक्का हो सकता है, जबकि मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में चरणबद्ध निवेश लंबी अवधि में फायदेमंद साबित हो सकता है।

"रोज़मर्रा के नेल कटर का छोटा सा रहस्य: ब्लेड पर क्यों होता है यह छेद?"

यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल, वह छोटा सा छेद मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि आप नेल कटर को चाबी के छल्ले, हुक, छोटी चेन या डोरी जैसी किसी चीज़ से जोड़ सकें। यह यात्रियों, पैदल यात्रियों, सैनिकों, नाविकों और उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने ग्रूमिंग टूल्स को वहीं रखना पसंद करते हैं जहां उन्होंने उन्हें रखा था। कुछ लोग नेल कटर को अपनी चाबियों पर ही रखते हैं, जो या तो बहुत ही सुविधाजनक है।

मुंबई की लोकल ट्रेन में कंगन बेचती बुजुर्ग का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनको देखने के बाद यूजर्स ने उन वीडियोज को काफी पसंद करते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। मीता तुषित शाह द्वारा साझा किए गए वीडियो में वह धीरे से उस कमजोर दिख रही महिला के पास जाती हैं और उनका नाम पूछती हैं। बुजुर्ग महिला, कमलाबेन मेहता ने जवाब देने से पहले बताया कि वह नालासोपारा में रहती हैं।वे बोलीं कि, 'मैं सब कुछ खरीदना चाहती थी लेकिन पैसों की कमी के कारण नहीं खरीद सकी। उसने बताया कि उसे अपने परिवार को रहने का खर्च देना था, लेकिन उसने अपना पता नहीं दिया ताकि परिवार को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वाकई महिला सशक्तिकरण का यही उदाहरण है।इस वीडियो को लगभग दो मिलियन बार देखा जा चुका था और सैकड़ों प्रतिक्रियाएं मिली थीं, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स उनके साहस की प्रशंसा कर रहे थे, जबकि अन्य लोग उसकी मदद के लिए आगे आ रहे थे।

राम चरण और उपासना के घर जुड़वा बच्चों का जन्म

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिदेला के घर खुशी का माहौल है, क्योंकि उनके यहां जुड़वा बच्चे (ट्विन्स) — एक बेटा और एक बेटी — का जन्म हुआ है। शनिवार ३१ जनवरी २०२६ को उनके घर नए मेहमान आए, और दोनों नवजात बच्चे तथा माँ स्वस्थ बताए जा रहे हैं।राम चरण के पिता और साउथ के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया (X) पर साझा किया और लिखा कि "बेहद खुशी और कृतज्ञता के साथ यह बताते हैं कि राम चरण और उपासना कोनिदेला को जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला है। माँ और दोनों बच्चे स्वास्थ्यपूर्ण हैं और पूरा परिवार इस दिव्य पल का आनंद ले रहा है।"राम चरण और उपासना ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को फैंस के साथ साझा किया। राम चरण ने लिखा कि "हम अपने बेटे और बेटी का स्वागत करते हुए बेहद आनंदित हैं। हमारा घर अब तीन बच्चों वाला हो गया है और हम अपने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद देते हैं।"उपासना ने इस मौके पर कहा कि यह उनके लिए "एक बड़ा सौभाग्य और आशीर्वाद" है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने तीनों बच्चों को प्यार, मजबूती और जिम्मेदारी के साथ पालने की कोशिश करेंगे, और इस खुशी में फैंस के स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट किया।राम चरण और उपासना ने जून २०१२ में शादी की थी और पहले उनके यहां पहली बेटी क्लीन कारा का जन्म जून २०२३ में हुआ था। जुड़वा बच्चों के आगमन के साथ अब उनका परिवार और भी बड़ा हो गया है, और फैंस तथा फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों ने उन्हें बधाइयाँ और शुभकामनाएँ भेजनी शुरू कर दी हैं।Celebrities और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपने शुभेच्छा संदेश साझा किए, जिसमें उन्होंने इस "wonderful addition" के लिए दंपति को शुभकामनाएँ दीं। इस खबर ने राम चरण के आने वाले प्रोजेक्ट्स और उनके पारिवारिक जीवन पर भी चर्चा को बढ़ावा दिया है।चिरंजीवी और उनकी पत्नी सुरेखा ने भी इस खुशी के मौके पर परिवार के लिए शुभकामनाएं साझा कीं और लिखा कि "हम बहुत गर्व और आनंद के साथ यह देख रहे हैं कि हमारे परिवार में नए सदस्य आए हैं। हम राम चरण और उपासना के साथ हमेशा खड़े हैं और उनके सभी प्रयासों में उनका समर्थन करेंगे।राम चरण और उपासना 9वीं क्लास से साथ पढ़ाई की थी, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों की सगाई दिसंबर 2011 में हुई और फिर 14 जून 2012 को दोनों ने हैदराबाद के टेंपल ट्रीज फार्म हाउस में शादी की। 20 जून 2023 को राम चरण की बेटी का जन्म हुआ था।

दिल्ली को स्वच्छ, बनाने के लिए MCD को ₹500 करोड़

CM रेखा गुप्ता का मास्टरप्लान

राजधानी दिल्ली को साफ-सुथरा, कचरा-मुक्त और धूल-प्रदूषण से मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी कदम उठाया है।

। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिल्ली नगर निगम (MCD) को ₹500 करोड़ की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस सहायता का लक्ष्य केवल सफाई व्यवस्था को सुधारना ही नहीं है, बल्कि नगर निगम की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना, कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाना और धूल-वायु प्रदूषण पर कड़ाई से नियंत्रण स्थापित करना भी है। इस घोषणा को राजधानी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में बड़ा ऐलान माना जा रहा है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सहायता राजधानी में साफ-सफाई और वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार का मानना है कि स्वच्छ वातावरण सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य, जीवन गुणवत्ता और सामाजिक कल्याण से जुड़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह फंड सही दिशा में खर्च किया जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।प्रधान रूप से यह ₹500 करोड़ की सहायता राशि कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर खर्च की जाएगी:

- सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई एवं धूल नियंत्रण: जहां नियमित धूल उड़ने की समस्या से वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- कचरा उठाने और प्रबंधन सेवाओं की मजबूती: कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों के पुराने बकाया भुगतान में से कुछ हिस्सा इससे निपटाया जाएगा, जिससे सेवाएँ निर्बाध रूप से जारी रह सकें।
- सड़कों की छोटी-मोटी मरम्मत और पैचवर्क: रोड पर फैली धूल कम करने के लिए आवश्यक मरम्मत का काम।
- धूल नियंत्रण के आधुनिक उपकरण और मिशन-ड्रिवन सफाई अभियानों में निवेश।

एमसीडी को दी जाने वाली यह सहायता एकमुश्त राशि है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आगे भी हर साल ₹300 करोड़ की स्थायी मदद देने का फैसला किया है, जिससे सफाई एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को दीर्घकालिक और टिकाऊ बनाया जा सके। यह स्थायी सहायता निगम की योजनाओं को मजबूत करेगा और सफाई ढांचे को लंबे समय तक सुदृढ़ बनाए रखने में मदद करेगा।इस पहल का लक्ष्य केवल कचरा उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी को धूल-प्रदूषण-मुक्त और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक हवा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। इसलिए सरकार धूल नियंत्रण के लिये पहले से चल रही योजनाओं को और अधिक संगठित तरीके से लागू करेगी।जिससे सफाई की दक्षता और गति दोनों बेहतर होंगी।

AI की सलाह पर HIV दवा लेना पड़ा भारी मरीज अस्पताल में भर्ती

राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने A I (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के उपयोग और दवा-खुद-लेने के खतरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक व्यक्ति ने एआई चैटबॉट से HIV से बचाव की दवा-सुझाव लेकर बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के ही दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभाव के कारण उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और उसे एक नामी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना एचआईवी जैसे संवेदनशील मामलों में स्व-दवाइकरण और तकनीक पर आंख बंद कर भरोसा करने के खतरों को उजागर कर रही है।पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, व्यक्ति ने एचआईवी के जोखिम के बाद एआई से जानकारी हासिल कर ली कि किन दवाओं का कोर्स लेना चाहिए। इसके बाद वह बिना परीक्षण और डॉक्टर की सलाह के स्थानीय मेडिकल स्टोर से HIV पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PEP) जैसी दवाइयाँ खुद ही ले आया और लगभग २८ दिनों का कोर्स शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही उसके शरीर में तीव्र दुष्प्रभाव उत्पन्न होने लगे और वह त्वचा तथा आंखों की समस्याओं से जूझने लगा।डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि इस तरह की गंभीर प्रतिक्रिया से निपटना मुश्किल होता है और मरीज की हालत फिलहाल निगरानी में गंभीर बनी हुई है।

आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान! ऑनलाइन बुक होंगे टिकट

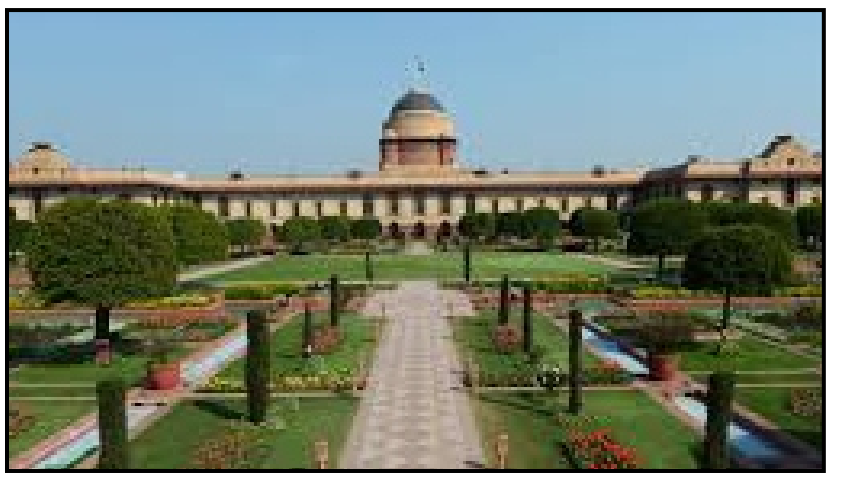

देश के प्रमुख सार्वजनिक उद्यान 'अमृत उद्यान' को अब सामान्य जनता के लिये भी खोला जा रहा है। लंबे समय से विशेष कार्यक्रमों और चयनित समूहों तक ही सीमित यह स्थल अब हर किसी के लिये खुला रहेगा, और इसके लिये टिकट व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से घर बैठे अपनी तिथि और समय चुनकर टिकट बुक कर सकें। यह निर्णय राजधानी में हरित क्षेत्र वृद्धि और पारिवारिक-सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है।अमृत उद्यान को अब सबके लिये सुलभ और व्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्यान में हरियाली, चलने-फिरने के रास्ते, खेल क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और वॉटर फाउंटेन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। सरकार और प्रशासन की योजना है कि यहाँ पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों, योग सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बच्चों के लिये सुरक्षित खेल क्षेत्र का आयोजन भी समय-समय पर किया जाएगा।इस नए परिवर्तन के तहत अब ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे लोग टिकट को मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर चुन सकते हैं, समय स्लॉट ले सकते हैं और QR कोड के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्थल पर लंबी कतारें, भीड़-भाड़ और टिकटिंग की परेशानियाँ काफी हद तक खत्म हो जाएँगी और आगंतुकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिये एक आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा,

बदलेगी यमुना नदी की तस्वीर — डीडीए ने जिम्मेदारी उठाई, निविदा जारी

राजधानी दिल्ली की जीवन-रेखा मानी जाने वाली यमुना नदी के निजामुद्दीन ब्रिज से डीएनडी फ्लाईवे तक के किनारों की तस्वीर अब बदलने वाली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इस क्षेत्र के पुनर्स्थापन और पुनर्जीवन के लिये बड़ा कदम उठाया है और इसके लिये परियोजना की निविदा (टेंडर) जारी कर दी गई है। इससे पूर्वायणदायी नदी के जीवनचक्र को सुधारा जाएगा और एक हरित, स्वच्छ, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनीष सिंघल ने बताया कि पिछले साल करीब 50 ट्रांसजेंडरों के सर्जिकल प्रोसीजर किए गए। इस साल इसे डबल करने की योजना है।विशेष रूप से यह काम उन बाढ़ मैदानों (फ्लडप्लेन्स) को पुनर्जीवित करेगा|

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार देर रात हुई बारिश और हल्की हवाओं ने राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंडक को और बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। रविवार सुबह भी रुक रुककर बारिश देखी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार, यह मौसमी हलचल अभी जारी रहने की उम्मीद है।मौसम विभाग के अनुसार, 1 से 7 फरवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इन विक्षोभों का प्रभाव न केवल मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में दिखेगा, बल्कि हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की भी उम्मीद है।

बीप-बॉप-बूप फेस्ट में उमड़ा बच्चों का उत्साह — साइंस, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन का मज़ेदार संगम

दक्षिणी दिल्ली के साकेत स्थित नेक्सस सिलेक्ट सिटीवॉक मॉल में बीप-बॉप-बूप फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने खेल-खेल में साइंस, टेक्नोलॉजी, रचनात्मकता और मनोरंजन को मज़े-से अनुभव किया। इस खास कार्यक्रम में ज्ञान को मज़ेदार और इंटरएक्टिव रूप में पेश किया गया, जिससे बच्चों का उत्साह और सीखने की रुचि दोनों ही बढ़ी।यह फेस्टिवल ३ से १६ साल तक के बच्चों के लिये तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य किताबों और स्क्रीन से बाहर निकलकर बच्चों को सीखने-का-अनुभव देना है। आयोजकों ने इसे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) से जुड़े ज्ञान को आसान और रोचक तरीके से पेश करने के लिये डिज़ाइन किया है, ताकि बच्चे खेल-खेल में सीखें और अपने अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाएँ।फेस्ट में मुख्य आकर्षणों में रोबोटिक्स और मशीनों का विशेष विज्ञान-और-टेक्नोलॉजी जोन शामिल था। इस जोन में बच्चों को लेगो से रोबोट बनाना, सूमो रोबोट मुकाबला, रोबोट फुटबॉल, और रिमोट-से चलने वाली गाड़ियों की प्रतियोगिताएँ जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलीं, जिनमें भाग लेकर बच्चों ने अनुभव-आधारित सीखने का आनंद लिया।भाग लेने वाले छात्रां में जहां कुछ ने कहा कि यह अनुभव बहुत मज़ेदार और ज्ञान-वर्धक रहा, वहीं कई अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। एक छात्र ने बताया कि वह "खेलते-खेलते नई चीजें सीख रहा है" और दूसरे ने कहा कि फेस्टिवल ने उनकी रचनात्मक सोच और तकनीकी समझ को बेहतर किया है। अभिभावकों ने भी यह कहा कि ऐसी गतिविधियाँ बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से दूर रखकर सीखने का सकारात्मक तरीका प्रदान करती हैं।

भारतीय किसान यूनियन ने शुरू की पदयात्रा"

किसानों की आवाज़ बुलंद

भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) की 'किसान क्रांति पदयात्रा' रविवार सुबह करीब 11 बजे गोसाईगंज ब्लॉक से शुरू हुई। भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा की अगुवाई में यह यात्रा अमेठी, गंगागंज, बहरौली, हरदोइया बाजार होते हुए नगराम पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। पहले दिन किसान लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। यह पदयात्रा 10 फरवरी को पीजीआई इलाके की वृंदावन योजना मैदान में आयोजित विशाल किसान महापंचायत के बाद समाप्त होगी। यात्रा का उद्देश्य किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ना है। सुबह से ही गोसाईगंज ब्लॉक क्षेत्र में हजारों किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया था। हाथों में झंडे, बैनर और तख्तियां लिए किसानों ने 'जय जवान-जय किसान' और 'किसान एकता जिंदाबाद' के नारे लगाए। यात्रा के मार्ग में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और किसान समर्थकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया।

पदयात्रा में प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा, मंडल महासचिव जगदीश द्विवेदी, मंडल मीडिया प्रभारी मुकेश द्विवेदी, लखनऊ जिलाध्यक्ष अनुरेन्द्र कुमार अन्नू, प्रदेश प्रवक्ता अनिल वर्मा, मंडल अध्यक्ष मोनिष खान, पंकज बाजपेई समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और हजारों किसान शामिल रहे। प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा ने कहा कि यह यात्रा किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने किसान आयोग के तत्काल गठन, किसानों के समस्त कर्ज माफ करने और उन्हें पूरी तरह मुफ्त बिजली देने की मांग की। वर्षों से गांवों में रह रहे गरीब और बेसहारा परिवारों को उजाड़ने की कार्रवाई बंद करने की भी मांग की। उन्होंने शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर रोक लगाने, निजी स्कूलों द्वारा धन उगाही बंद करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ऋषि मिश्रा ने निजी अस्पतालों की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण और आम मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने और गरीब किसानों के प्रति पुलिस व प्रशासन के व्यवहार में सुधार की भी मांग की।

"विभाजनकारी शक्तियों पर सख्त रुख: सीएम योगी बोले—एकता के खिलाफ किसी साजिश को नहीं उठने देंगे"

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाराबिरवा, कानपुर रोड स्थित संत रविदास मठ में संत रविदास जी की प्रतिमा व सभागार का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि संत रविदास का प्रकटीकरण 649 वर्ष पहले काशी के सीर गोवर्धन में हुआ था। इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से आलोकित होकर यह समाज 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है। संत रविदास का जब धराधाम पर प्रकटीकरण पर हुआ, तब देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था। उन्होंने उस समय भी साधना की पवित्रता और उसे कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य किया था। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता, मन की शुद्धता को महत्व देता है और लोककल्याण के प्रति आग्रही बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के मन में महापुरुषों, संतों के प्रति मन में श्रद्धा व आदर का भाव होना चाहिए। विभाजनकारी ताकतें बांटेंगी, लेकिन गुलामी कालखंड का स्मरण करते हुए उन्हें सिर उठाने का अवसर नहीं देना है। उन्होंने कहा कि संतों की दिव्य साधना से प्राप्त सिद्धि का प्रतिफल देश को मिलेगा। हम सभी को देश की एकता व संप्रभुता के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रदेश में सनातन धर्म से जुड़े धर्मस्थलों-महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, संत तुलसीदास का राजापुर, मां विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट, अयोध्या, शुकतीर्थ, नैमिषारण्य, मथुरा-वृंदावन, भगवान बुद्ध से जुड़े बौद्ध सर्किट समेत लगभग 1200-1500 स्थानों के पुनरोद्धार के कार्य किए गए। मुख्यमंत्री योगी ने समाज में भेदभाव का आरोप लगाने वालों को भी आईना दिखाया। बोले- "जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ने के लिए मध्य काल में अलग-अलग जातियों से 12 शिष्य बनाए। समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य उस कालखंड में संतों ने किया, वह अद्भुत था। वर्तमान भारत का निर्माण उसी नींव पर हुआ है। गुलामी के बंधन को तोड़ने में वही हमारी प्रेरणा रही है।" सीएम योगी ने कहा कि संत रविदास ने प्रेरणा दी कि ऐसा राज होना चाहिए, जहां सभी को अन्न प्राप्त हो, कोई भूखा न सोए। हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कर्म साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया।

"लेदर सेक्टर को नई रफ्तार: IGCR स्कीम से बंद इकाइयों में जगी फिर से उम्मीद"

कानपुर और उसके आसपास करीब एक हजार छोटी-बड़ी लेदर इकाइयां संचालित हैं, जिनमें से कई पर बंदी का संकट बना हुआ था। हालांकि, हाल के महीनों में यूरोपीय देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों और अब बजट में घोषित राहतों से उद्योग के दोबारा पटरी पर लौटने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। उद्योग जगत ने बजट में आईजीसीआर स्कीम के विस्तार का स्वागत किया है।

कानपुर केंद्रीय बजट ने कानपुर की लेदर इकाइयों को आईजीसीआर स्कीम में शामिल कर और समयसीमा बढ़ाकर बड़ी व्यापारिक राहत प्रदान की है। शू अपर एक्सपोर्टर्स को मिली नई छूट से 222 मिलियन डॉलर के मौजूदा निर्यात कारोबार को वैश्विक स्तर पर बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलेगा। कानपुर में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आम आदमी से लेकर कारोबारी और उद्योग जगत की नजरें टिकी हुई थीं। बजट को कुल मिलाकर विकास को गति देने वाला माना जा रहा है। खास तौर पर लेदर (चर्म) इंडस्ट्री के लिए किए गए प्रावधानों से कानपुर और आसपास की दम तोड़ती उद्योग इकाइयों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। कानपुर और उसके आसपास करीब एक हजार छोटी-बड़ी लेदर इकाइयां संचालित हैं, जिनमें से कई पर बंदी का संकट बना हुआ था। हालांकि, हाल के महीनों में यूरोपीय देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों और अब बजट में घोषित राहतों से उद्योग के दोबारा पटरी पर लौटने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। उद्योग जगत ने बजट में आईजीसीआर स्कीम के विस्तार का स्वागत किया है। कस्टम नोटिफिकेशन नंबर 2/2026 के तहत शू अपर एक्सपोर्टर्स को इस योजना में शामिल किया गया है। पहले यह सुविधा लेदर गारमेंट्स, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स तक सीमित थी। उद्यमियों का मानना है कि इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2024-25 में शू अपर का निर्यात 222 मिलियन डॉलर रहा था। इसके साथ ही आईजीसीआर के तहत निर्यात की समयसीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने और योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को भी राहत भरा कदम बताया गया है। टैग, लेबल, स्टिकर और बेल्ट जैसे आयातित सामान पर कस्टम ड्यूटी छूट बढ़ाए जाने से भी उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जावेद इकबाल, पूर्व रीजनल चेयरमैन, चर्म निर्यात परिषद ने कहा कि बजट में आईजीसीआर स्कीम का विस्तार और यूरोपीय बाजारों में मिली राहत से कानपुर के पारंपरिक लेदर उद्योग को नई दिशा मिलेगी। इससे निर्यात और रोजगार दोनों

"रविदास जयंती समारोह में अफरा-तफरी: श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच घुसा सांड"

वाराणसी में संत रविदास की जयंती के अवसर पर संत रविदास मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान वाराणसी नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब एक सांड मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच घुस आया। अचानक भीड़ में सांड के आने से अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्रद्धालु दर्शन और पूजा में लगे थे, तभी अचानक सांड भीड़ में पहुंच गया। सांड को देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे और कई लोग घबराकर अपने परिजनों को तलाशने लगे। स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद सेवादारों और आयोजन में लगे कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाई। उन्होंने सूझबूझ और सावधानी के साथ सांड को घेरकर धीरे-धीरे मंदिर परिसर से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस घटना में किसी श्रद्धालु को गंभीर चोट नहीं आई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि, इतनी बड़ी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान आवारा पशुओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। संत रविदास जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग घंटों इंतजार करके संत रविदास के दर्शन कर रहे हैं। करीब एक हजार से ज्यादा NRI 10 चार्टर्ड विमानों से आए। उन्होंने संत रविदास को डॉलर की माला पहनाई।

"उन्नाव में हादसा: नाले में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत"

उन्नाव जिले में एक मजदूर की नाले में गिरने से मौत हो गई। यह घटना पुरवा कोतवाली क्षेत्र के कालू खेड़ा रोड पर गया प्रसाद खेड़ा के पास हुई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय राम बाबू पुत्र सुंदर लाल के रूप में हुई है, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार, राम बाबू सरवन स्थित सेंट्रल बैंक से रुपये निकालकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उनके साथ उनका दोस्त सज्जन भी था, जो रुपये निकालने में उनकी मदद करने गया था। हादसे के बाद से परिवार ने सज्जन की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया है। पुरवा–कालू खेड़ा मार्ग पर गया प्रसाद खेड़ा के पास लौटते समय राम बाबू की मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। उनकी बाइक सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुरवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। मृतक राम बाबू के परिवार में उनकी पत्नी और दो छोटे बेटे हैं। वह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी असामयिक मृत्यु से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है।

बजट 2026 में यूपी को बड़ी सौगात —

रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर केंद्रित योजनाओं का ऐलान

बजट 2026 – 27 से उत्तर प्रदेश को व्यापक विकास का अवसर मिला है, जिसमें नए निवेश, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार तथा बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं। इन घोषणाओं से राज्य की लॉन्ग-टर्म प्रगति और राष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क में प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी मजबूत होगी।

बजट 2026 में यूपी को बड़ी सौगात — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश (UP) के लिए कई बड़े एलान और घोषणाएँ की गईं हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास, बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। इन घोषणाओं से प्रदेश में नया निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।सबसे बड़ी घोषणा यूपी को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की है। बजट में वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम को आगे बढ़ाने का एलान किया गया है, जिससे उत्तर भारत के पूर्वोत्तर और यूपी के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी।इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर जिले में महिलाओं के लिये सशक्तिकरण योजनाएँ और महिला-उन्मुख कार्यक्रम शामिल हैं, जिनके तहत महिलाओं के लिये स्टार्ट-अप समर्थन, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जायेगा।बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये भी खास प्रावधान किये गए हैं। जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के लिये इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना की जाएगी, जिससे आकस्मिक चिकित्सा सहायता तेज़ और प्रभावी होगी।

औद्योगिक विकास के लिये बजट ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की है, जिससे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को निवेश एवं विस्तार के लिये अनुकूल माहौल मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में व्यापक विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है।यूपी के लिये कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षेत्र में भी बड़े निवेश की संभावनाएँ हैं। बजट में कुशीनगर से बांगकॉक तक नई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर जोर दिया गया है, जिससे राज्य के विश्व पर्यटन और व्यापार नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

ये घोषणाएँ ऐसे समय में आई हैं जब उत्तर प्रदेश के लिये केंद्रीय फंड और सहायता में वृद्धि की उम्मीदें जताई जा रही थीं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार यूपी को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपये तक का शेयर मिलने की सम्भावना है, जो पिछली तुलना में करीब 8 प्रतिशत अधिक हो सकती है।

विश्लेषकों का कहना है कि बजट की ये घोषणाएँ उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचे (इनफ्रास्ट्रक्चर) की दिशा में राज्य को अग्रसर करेंगी, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन जैसे सेक्टरों में समग्र विकास को बल देंगी। इससे न सिर्फ निवेशकर्ता आकर्षित होंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।बजट 2026 – 27 से उत्तर प्रदेश को व्यापक विकास का अवसर मिला है, जिसमें नए निवेश, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार तथा बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं। इन घोषणाओं से राज्य की लॉन्ग-टर्म प्रगति और राष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क में प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी मजबूत होगी।

KGMU के डॉक्टरों ने 'चमत्कारी' सर्जरी से 3-साल की बच्ची की जान बचाई

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ के न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर तीन-साल की बच्ची की जान बचाई है। बच्ची के सिर में फँसी गोली लगातार अपनी जगह बदल रही थी, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों ने करीब चार घंटे तीस मिनट तक चली सर्जरी में सफलता हासिल की। यह ऑपरेशन चिकित्सीय क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।घटना तब हुई जब बच्ची घर की छत पर खेल रही थी और अचानक उसे गोली लग गयी। शुरुआती जांच में परिवार ने मामूली चोट समझी थी, लेकिन बाद में पता चला कि गोली सिर के अंदर दिमाग में घुस गयी है और वह लगातार दूसरी जगह पर घूम रही थी। बच्ची को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से स्थिति गंभीर होने पर उसे KGMU रेफर किया गया।डॉक्टरों की टीम, जिनका नेतृत्व डॉ. अंकुर बजाज ने किया, ने बेहद सावधानी और विशेषज्ञता के साथ यह ऑपरेशन सफल बनाया। उन्होंने बताया कि गोली का दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्सों के पास घूमना इस सर्जरी को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता था, लेकिन टीम के समन्वय और कौशल से गोली सफलतापूर्वक बाहर निकाली गयी। बच्ची अब स्थिति में सुधार दिखा रही है|

आगरा में न्यायिक अधिकारी को धमकी, 10 लाख की रंगदारी मांगी गई

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक गंभीर सुरक्षा मामला सामने आया है, जहाँ एक न्यायिक अधिकारी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई और उनसे १० लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। यह घटना २९ जनवरी की रात को हुई जब आरोपी ने तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल करते हुए दुर्व्यवहार भी किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हरीपर्वत थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़ित अधिकारी अतिरिक्त सिविल जज (ACJM) बटेश्वर कुमार को फोन पर धमकी दी गई कि यदि उन्होंने १० लाख रुपये नहीं दिए, तो उनकी जान को खतरा है। धमकी भरी कॉलों में गाली-गलौज और डराने-धमकाने वाला भाषा भी इस्तेमाल किया गया, जिससे अधिकारी और उनके परिवार में चिंता की स्थिति बन गई।आगरा पुलिस अब फोन करने वाले नंबरों को ट्रेस करने और अपराधी को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। जांच में साइबर सेल और तकनीकी टीम भी लगे हैं ताकि कॉल के स्रोत का पता लगाया जा सके और घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरह की धमकियां कानून-व्यवस्था को चुनौती देती हैं और इसे ख़त्म करने के लिये कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। मामले में धमकी देने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर योगी सरकार का मेगा पुश

यह भूमि आवंटन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों को शामिल करता है, जिससे यह क्षेत्र औद्योगिक हब के रूप में और मजबूती से उभरने की दिशा में अग्रसर है। इन इकाइयों के लिए जमीन आवंटित करने से निवेशकों के लिए निर्माण शुरू करने का रास्ता साफ़ हुआ है और प्रदेश के आर्थिक वातावरण में उत्साह की लहर देखने को मिल रहीहै।सरकार की योजना के तहत, यह देखा जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार न केवल आर्थिक गतिविधियों को अधिक संगठित रूप से जोड़ देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। इससे बेरोज़गारी में कमी आने की उम्मीद है और राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।विशेष रूप से, सेमीकंडक्टर और उच्च तकनीकी उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, जो नई तकनीकी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने का अवसर देगा।